My Notes
राष्ट्रीय

टीकों की निगरानी व्यवस्था पर डब्लूएचओ की मुहर

भारत में टीकों पर निगरानी की व्यवस्था पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने अपनी मुहर लगा दी है। डब्लूएचओ की अंतरराष्ट्रीय टीम ने ग्लोबल बेंचमार्किंग टूल के आधार पर पांच दिन की समीक्षा के बाद इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक सही पाया है। डब्लूएचओ के प्रीक्वालिफिकेशन प्रोग्राम (पीक्यूपी) में सफल रहने के बाद अब भारतीय टीका उद्योग को और मजबूती मिल सकेगी।

क्या है?

1. डब्लूएचओ ने इस परीक्षण में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के साथ ही राज्यों की निगरानी व्यवस्था और इन टीकों के असर पर नजर रखने वाली व्यवस्था को भी शामिल किया था।
2. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सीके मिश्रा ने कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि है। इस लिहाज से बहुत गंभीर प्रयासों के आधार पर लंबी कोशिशों के जरिए पूरी व्यवस्था में सुधार किया गया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े टीका निर्माता देशों में है और यहां से 150 से ज्यादा देशों को बहुत बड़ी मात्रा में टीके निर्यात होते हैं।
3. डब्लूएचओ की ओर से टीकों के राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (एनआरए) को दी गई स्वीकृति के बाद भारतीय टीकों की गुणवत्ता को ले कर दुनिया भर के देश आश्वस्त हो सकेंगे। डब्लूएचओ के भारत प्रतिनिधि बेंक हेकडम ने इस मौके पर कहा, 'वैश्विक स्वास्थ्य में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिहाज से यह बहुत अहम कदम है। खास तौर पर दवा उद्योग और नियामक क्षमता को को मजबूत करने के लिहाज से।'
4. दुनिया भर में सप्लाई के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां भी बड़ी मात्रा में टीकों की खरीद करती हैं। डब्लूएचओ की ओर से भारतीय नियामक व्यवस्था को सही पाए जाने के बाद अब ये एजेंसियां यहां से इन टीकों को सीधे खरीद सकेंगी।
5. भारत में टीका बनाने वाली 21 बड़ी इकाइयां चल रही हैं। इससे भारत के टीका निर्माण उद्योग को और मजबूती मिल सकेगी। डब्लूएचओ अपने इस प्रीक्वालिफिकेशन प्रोग्राम (पीक्यूपी) में टीकों की गुणवत्ता, सुरक्षा और असर का भी आकलन करता है।

तृतीय राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन आयोजित

उत्तराखंड जल विद्युत निगम एवं आईआईटी रूड़की के सहयोग से केन्द्री य जल आयोग द्वारा आयोजित तृतीय राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन रूड़की में सम्पन्न हो गया। इस सम्मेलन में बांध सुरक्षा के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जिनका सामना वर्तमान में जारी बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के कार्यान्वयन में करना पड़ रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं विदेशी विशेषज्ञों द्वारा ज्ञान, अनुभव, नवोन्मेषन, नवीन प्रौद्योगिकियों आदि साझा किये जाने से बांध डिजाइन, निर्माण, परिचालन एवं रख-रखाव से जुड़ी अनिश्चितताओं को कारगर ढंग से प्रबंधित करने के लिए कार्य नीतियों को आकार देने में और मदद मिली।

क्या है?

1. इस सम्मेलन को काफी उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, जिसमें 400 से अधिक शिष्टमंडलों ने भाग लिया तथा देश के भीतर और देश के बाहर के विशेषज्ञों के 70 से अधिक तकनीकी शोधपत्र प्रस्तुत किये गये। लगभग 40 राष्ट्रीय एवं विदेशी संगठनों ने सम्मेलन स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी के जरिए अपनी प्रौद्योगिकियों, उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदर्शित किया।
2. इस समारोह में अमरीका, आस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेलन, नीदरलैंड तथा जर्मनी के पेशेवर व्यक्तियों ने हिस्सों लिया।

देश का पहला 4डी संग्रहालय

स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मौजूदा पीढ़ी को अवगत कराने के लिए गुजरात के कच्छ-भुज में पहला 4डी संग्रहालय 'वंदेमातरम मेमोरियल' स्थापित किया गया है। 12 एकड़ क्षेत्र में फैले इस संग्रहालय का पहला ढांचा संसद भवन जैसा, जबकि दूसरा लाल किले जैसा है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

क्या है?

1. ब्रिटिश शासन से भारत को आजाद कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिया, मौजूदा पीढ़ी का उससे अवगत होना जरूरी है।
2. संग्रहालय का पहला ढांचा एक लाख वर्गफुट में है, जो भारत के संसद भवन की प्रतिकृति है। संग्रहालय का दूसरा ढांचा 50 हजार वर्गफुट का है, जो लालकिले जैसा है और उसमें गांधी आश्रम ऑडिटोरियम गैलरी लाइब्रेरी फूडकोर्ट का समावेश है।
3. इस मेमोरियल की इमारत बनाने में उसी खान के पत्थरों का उपयोग किया गया, जिसका संसद भवन के निर्माण में किया गया था। यह मेमोरियल आशापुरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीएसआर का हिस्सा है।
4. आशापुरा फाउंडेशन के चेयरमैन चेतन शाह ने कहा कि, इस संग्रहालय में शहीद भगत सिंह, मंगल पांडेय, महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का चित्रण किया गया है। प्रौद्योगिकी के सहयोग से इतिहास को यहां जीवंत दर्शाया गया है।
5. इसमें शहंशाह जहांगीर के दरबार में ब्रिटिशों के आगमन, दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में बापू को सत्ता सौंपने जैसे अवसर यहां जीवंत बनाए गए हैं।
6. दुनिया में अपनी तरह के पहले इस स्मारक का हाल ही में मुंबई के रवींद्र नाट्य मंदिर में प्री–लांच किया गया था।

गरीबों के लिये याचिका दाखिल करना हुआ आसान

मध्यम और गरीब आय वर्ग के लोगों के लिये देश की कानूनी सहायता लेना आसान हो गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्यम आय समूह योजना लागू की है। यह आत्म समर्थन देने वाली योजना है और इसके तहत 60,000 रुपए प्रति महीने और 7,50,000 रुपए वार्षिक आय से कम आय वाले लोगों के लिये कानूनी सहायता दी जाएगी।

क्या है?

1. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860(2) के अन्तगर्गत सोसायटी के प्रबंधन का दायित्वों गवर्निंग बॉडी के सदस्यों को दिया गया है।
2. गवर्निंग बॉडी में भारत के प्रधान न्यायाधीश संरक्षक होंगे। अटार्नी जनरल पदेन उपाध्यक्ष होंगे। सॉलिसीटर जनरल ऑफ इंडिया मानद सदस्य होंगे और उच्चतम न्यायालय के अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य होंगे।
3. उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार न्यायालय के समक्ष याचिका केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिये दाखिल की जा सकती है।
4. सेवा शुल्का के रूप में उच्चतम न्यायालय मध्य आय समूह कानूनी सहायता सोसायटी (एससीएमआईजीएलएएस) को 500 रुपए का भुगतान करना होगा। आवेदक को सचिव द्वारा बताई गई फीस जमा करानी होगी।
5. यह योजना में संलग्न अनुसूची के आधार पर होगी। एमआईजी कानूनी सहायता के अंतर्गत सचिव याचिका दर्ज करेंगे और इसे पैनल में शामिल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड/दलील पेश करने वाले वकील/वरिष्ठ अधिवक्ता को भेजेंगे। यदि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इस बात से संतुष्ट हैं कि यह याचिका आगे की सुनवाई के लिये उचित है, तो सोसायटी आवेदक के कानूनी सहायता अधिकार पर विचार करेगी। जहाँ तक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक की पात्रता का प्रश्न है, तो याचिका के बारे में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की राय अंतिम राय मानी जाएगी।
6. योजना के अंतर्गत मध्यम वर्ग के वैसे लोग जो उच्चतम न्यायालय में मुकद्दमों का खर्च नहीं उठा सकते, वे कम राशि देकर सोसायटी की सेवा ले सकते हैं। इस योजना के लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित फार्म भरना होगा और इसमें शामिल सभी शर्तों को स्वीकार करना होगा।
7. योजना के अनुसार याचिका के संबंध आने वाले विभिन्नि खर्चों को पूरा करने के लिये आकस्मिक निधि बनाई जाएगी। याचिका की स्वीकृति के स्त्र तक आवेदक को इस आकस्मिक निधि में से 750 रुपए जमा कराने होंगे। यह सोसायटी में जमा किये गए शुल्क के अतिरिक्त होगा। यदि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यह समझते हैं कि याचिका आगे अपील की सुनवाई योग्य नहीं है, तो समिति द्वारा न्यूनतम सेवा शुल्क के तौर पर लिये गए 750 रुपए को घटाकर पूरी राशि चेक से आवेदक को लौटा दी जाएगी।

भारत का एकमात्र जिंदा ज्वालामुखी सक्रिय हुआ

भारत का एकमात्र जिंदा ज्वालामुखी फिर सक्रिय हो गया है। अंडमान–निकोबार द्वीप स्थित बैरन ज्वालामुखी में 150 साल बाद पहली बार 1991 में गतिविधि देखी गई थी। अब वैज्ञानिकों ने फिर उसे लावा उगलते पाया है। गोवा स्थित नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसनग्राफी (एनआईओ) के शोधकर्ताओं ने कहा कि इससे राख निकल रहा है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

क्या है?

1. सीएसआईआर-एनआईओ ने संयुक्त बयान में कहा, 'अंडमान-निकोबार पर जिंदा ज्वालामुखी फिर से भड़क गया है। पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर उत्तर-पूर्व स्थित ज्वालामुखी 150 साल से शांत पड़ा है, जो पहले 1991 में सक्रिय हुआ था और उसके बाद से इसमें रुक-रुक कर गतिविधि दिखी है।'
2. अभय मुधोल्कर के नेतृत्व वाली एसआईआर-एनआईओ के वैज्ञानिकों की टीम ने बताया कि ज्वालामुखी फिर सक्रिय हुआ है और इससे धुआं तथा लावा निकल रहा है।
3. एनआईओ ने कहा, '23 जनवरी 2017 की दोपहर एसआईआर-एनआईओ के जहाज पर बैठे शोधकर्ताओं ने बैरन ज्वालामुखी के नजदीक समुद्र तल से उस वक्त नमूने लिए जब इससे अचानक राख निकलना शुरू हुआ।'
4. 'टीम ज्वालामुखी के करीब एक मील दूर थी और इसे बहुत बारीकी से देख रही थी। यह 5-10 मिनट तक रह-रह कर भड़कता रहा।' सूर्यास्त होने के बाद टीम ने देखा कि इससे लाल लावा भी निकलना शुरू हुआ। एनआईओ का कहना है कि शोधकर्ता 26 जनवरी की सुबह फिर ज्वालामुखी की गतिविधियों को देखने गए। शोधकर्ताओं की टीम ने पाया कि उसमें विस्फोट हो रहा था और उससे धुआं निकल रहा था।
5. शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि धुएं के कारण ज्वालामुखी के मुख के ऊपर बादल घिरे दिख रहे थे, वहीं उससे दूर के हिस्से का आसमान पूरी तरह साफ था।

भारतीय नौसेना की 'तारिणी'

आईएनएस मंडोवी बोट पूल पर आयोजित होने वाले समारोह में दूसरी सागर नौका 'तारिणी' को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।

क्या है?

1. समुद्री नौवहन गतिविधियों और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने विश्व के पहले भारतीय महिला परिनौसंचालन अभियान की परिकल्प ना की है।
2. इस परियोजना के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी के नेतृत्व में 6 महिला अधिकारियों के दल का चयन किया गया है। इन अधिकारियों ने आईएनडब्यू का टीसी, मुंबई में नौवहन का मौलिक प्रशिक्षण लिया है।
3. आईएनएसीवी तारिणी का निर्माण गोवा की मैसर्स एक्वेरियस शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड ने किया है।
4. नौका तारिणी को भारतीय नौसेना द्वारा परिकल्पित, विश्व के पहले महिला परिनौसंचालन अभियान के लिए रखा गया है।
5. एल्युमिनियम और स्टीदल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन के लिए नौका का ढांचा लकड़ी और फाइबर ग्लास से बना है।
6. आईएनएसवी तारिणी में 6 सूट हैं। नवनिर्मित आईएनएसवी तारिणी के ट्रायल 30 जनवरी, 2017 को सफलतापूर्वक संपन्न हो गए थे।
7. तारिणी में कुल छह पाल लगे हैं जो इसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सफर तय करने की ताकत देते हैं।
8. अत्याधुनिक सेटेलाइट सिस्टम के जरिये तारिणी के क्रू से दुनिया के किसी भी हिस्से में संपर्क किया जा सकता है।
9. 'महादेई' के बाद 'तारिणी' भारतीय नौसेना की गहरे समंदर में उतर सकने वाली दूसरी सेलबोट अर्थात् नौकायन पोत है।
10. इसकी तकनीक विकसित करने में महादेई को चलाने का अनुभव खास काम आया है।
11. इस नौका का डिजाइन ओडिसा के गंजम जिले के प्रसिद्ध तारा तारिणी मंदिर से प्रेरित है।
12. 'तारिणी' शब्द का अर्थ होता है 'नौका' और संस्कृत में इसका मतलब होता है 'तारने वाली'।

किशोरों को मिलेगा अब सच्चा 'साथिया'

किशोरों के अंदर हो रहे कई तरह के बदलाव और उनके मन में उठने वाले तमाम सवालों को ले कर अब उन्हें ज्यादा सही सलाह मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने 'साथिया' कार्यक्रम को और मजबूती दी है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के तहत सक्रिय हरेक 'साथिया' किशोर कार्यकर्ता को अब सरकार अलग से एक रिसोर्स किट उपलब्ध करवाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सीके मिश्र ने साथिया रिसोर्स किट जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा किशोर आबादी है, जो दुनिया में किसी भी देश की किशोर आबादी से अधिक है।

क्या है?

1. किशोरों के मन में उठते तमाम सवालों का उन्हें जवाब मिलना बेहद जरूरी है। इस काम के लिए सबसे प्रभावी तरीका यही हो सकता है कि उनके साथी किशोर ही उन्हें इस बारे में सही वैज्ञानिक जानकारी दें। इसलिए किशोरों के बीच से ही साथिया कार्यकर्ता चुने गए हैं।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

2. रिसोर्स किट उन्हें इस काम के लिए ज्यादा समर्थ बनाएगी। यह पहल राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के तहत की गई है। इसके तहत मुख्य रूप से किशोरों के पोषण, सेक्स और प्रजनन संबंधी मुद्दे, गैर संक्रामक बीमारियों, नशे के खतरे, हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरुक करने पर जोर दिया जा रहा है।
3. किशोरों के मन में उठने वाले सवालों के जवाब के लिए 'साथिया सलाह' मोबाइल ऐप भी उपलब्ध करवाया गया है। इसे गूगल प्लेस्टोर से इसे मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है।
4. 'भ्रांति-क्रांति' नाम से एक खेल विकसित किया गया है। एक किताब में लोगों के सहज सवाल और उनके जवाब दिए गए हैं। इसी तरह एक डायरी दी गई है, जिसमें वह साथियों के साथ साझा की गई जानकारी के बारे में सूचना दर्ज कर सकते हैं।

360 डिग्री घुमाव वाली चेतावनी प्रणाली विकसित करेगा भारत

वायुसेना में पहले स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (एईडब्ल्यूसीएस) 'नेत्र' शामिल होने के बाद डीआरडीओ इसके उन्नत संस्करण को विकसित करने की तैयारी कर रहा है। उन्नत संस्करण 360 डिग्री घुमाव वाला होगा। जबकि मौजूदा संस्करण 240 डिग्री घूमने में सक्षम है।

क्या है?

1. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अध्यक्ष एस. क्रिस्टोफर ने कहा कि अगला संस्करण अधिक रेंज और 360 डिग्री कवरेज के साथ उन्नत किया जाएगा। फिर भारत इजरायल के बाद 360 डिग्री घुमाव वाली प्रणाली विकसित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा।
2. वर्तमान प्रणाली 'नेत्र' ब्राजीलियाई विमान एम्ब्रेयर-145 में लगाया गया है। यह केवल विमान के अगल-बगल के क्षेत्र को स्कैन कर सकता है और आगे और पीछे के क्षेत्र को नहीं।
3. जबकि 360 डिग्री वाली प्रणाली आगे और पीछे भी कवर करेगी। क्रिस्टोफर ने कहा कि इसका यह मतलब नहीं नहीं कि मौजूदा प्रणाली में कोई कमी है।
4. इजरायल को छोड़कर दुनिया के देशों में सीमित क्षेत्र कवर करने वाली प्रणाली ही है। उन्होंने कहा कि सीमा पर निगरानी के दौरान यह दोनों क्षेत्र स्कैन कर सकता है।
5. 360 डिग्री का स्कैन केवल समुद्र में ही जरूरी होता है। डीआरडीओ प्रमुख ने कहा कि अगला संस्करण सात साल के भीतर तैयार हो जाएगा। दो और एम्ब्रेयर एईडब्ल्यूसीएस से लैस किए जा रहे हैं।
6. इनमें से एक को जून में वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। जबकि दूसरे को और सुधार के बाद वायुसेना को सौंपा जाएगा।

नोटबंदी की एसआइटी की अर्जी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया, जिसमें सरकार के नोटबंदी के फैसले की एसआइटी से जांच कराने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एसके कौल की पीठ ने याचिका खारिज की।

क्या है?

1. याचिका में 500 और 2000 रुपये के जारी नए करेंसी नोटों पर 'स्वच्छ भारत' का लोगों भी हटाने की मांग की गई थी।
2. पीठ ने कहा, 'नोटबंदी' के मुद्दे को लेकर दायर कई याचिकाओं पर हम पहले से ही सुनवाई कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) को नोट पर लोगों का फैसला लेने के लिए आपसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।
3. याचिका हंस राज जैन द्वारा दायर की गई थी। इसमें आठ नवंबर, 2016 को केंद्र के नोटबंदी के फैसले की एसआइटी से जांच कराने के साथ ही एटीएम से पैसे निकालने के लिए लंबी-लंबी लाइनों में खड़े रहने के दौरान जिन लोगों की मौत हो गई थी, उनके परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की गई थी।

'उदय' योजना में शामिल होने वाला 22वां राज्य

भारत सरकार और सिक्किम ने उज्जवल डिस्कॉम एश्योनरेंस योजना (उदय) के तहत राज्य के बिजली वितरण विभाग के परिचालन में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर हस्ताक्षर करने के साथ ही उदय के अंतर्गत आने वाले राज्यों की संख्या 22 हो गयी है। सिक्किम किफायती कोषों, एटी एंड सी में कमी और ट्रांसमिशन की खामी, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने जैसे तरीकों से 'उदय' के माध्यम से 481 करोड़ रूपए का कुल लाभ अर्जित करेगा।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

क्या है?

1. एमओयू से राज्य के बिजली वितरण विभाग की परिचालन क्षमता में सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। बदलाव की प्रक्रिया के दौरान उत्तगर प्रदेश और डिस्कॉम्स अनिवार्य फीडर और ट्रांसफामर्स मीटरों का वितरण, उपभोक्ता इंडेक्स एवं नुकसान की जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड/बदलना, मीटर इत्यागदि, बड़े ग्राहकों के लिए समार्ट मीटरिंग जैसे कदमों के जरिए परिचालन दक्षता लाने का प्रयास करेंगे।
2. इससे पारेषण (ट्रांसमिशन) और एटीएंडसी के नुकसान को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा बिजली की आपूर्ति और वसूली के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सकेगा। इस दौरान एटीएंडसी और ट्रांसमिशन नुकसान में क्रमशः 15 प्रतिशत और 3.50 प्रतिशत की कमी लाकर 453 करोड़ रूपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सकेगा।
3. 'उदय' के तहत ध्यान दिए जाने वाले बिंदुओं में से ऊर्जा दक्षता एक है। पीक लोड घटाने और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए सिक्किम सरकार ऊर्जा दक्षता वाले एलईडी बल्बों, कृषि पंपों, पंखों एवं एयर कंडीशनरों, कुशल औद्योगिक उपकरणों को पीएटी (परफार्म, एचीव, ट्रेड) के जरिए बढ़ावा देगी। इससे लगभग 25 करोड़ रूपए की बचत होने का अनुमान हैं।
4. एक तरफ जहां राज्य सरकार द्वारा डिस्कॉएम्स की परिचालन दक्षता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं और आगे बिजली आपूर्ति की लागत घटाई जाएगी वहीं केंद्र सरकार भी राज्य में बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार और आगे बिजली की लागत को कम करने के लिए डिस्कॉम्स और राज्यन सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
5. डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस जैसी केंद्रीय योजनाएं, ऊर्जा क्षेत्र विकास निधि अथवा ऊर्जा मंत्रालय की अन्य योजनाएं और एमएनआरई, राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पहले से ही धन उपलब्ध करा रही हैं। अगर राज्यय/डिस्कॉम्सन योजनाओं के तहत निर्धारित परिचालन लक्ष्य को प्राप्ता करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त/प्राथमिकता के आधार पर भी अनुदान उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।
6. इस एमओयू पर हस्ताक्षर होने का सबसे बड़ा लाभ सिक्किम के लोगों को होगा। डिस्कॉथम्सर द्वारा बिजली की उच्च मांग का अर्थ उत्पादन इकाइयों में अधिक पीएलएफ से होगा और ऐसा इसलिए बिजली की प्रति यूनिट की कम लागत का लाभ उपभोक्ता ओं को मिलेगा।
7. डिस्कॉम्सच एटीएंडसी नुकसान वाले क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि करेगा। इस योजना से सिक्किम के अब भी बिजली से महरूम घरों में किफायती और त्वरित बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
8. बिजली से दूर गांवों/परिवारों को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति से अर्थव्यवस्था को बल और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसरों में सुधार आयेगा और राज्य के लोगों के जीवन में सुधार आएगा।

'बेट द्वारिका दर्शन सर्किट' का विकास

शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही में केन्द्रीय योजना 'धरोहर शहर विकास और संवर्द्धन योजना (हृदय)' के तहत 16.27 करोड़ रुपये की लागत से गुजरात में 6 किलोमीटर लंबे बेट द्वारिका दर्शन सर्किट के विकास को मंजूरी दी है। राजीव गाबा की अध्यक्षता वाली हृदय राष्ट्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने गुजरात के द्वारिका जिले में प्रसिद्ध द्वारिकाधीश हवेली और हनुमान दांडी को आपस में जोड़ने वाले सर्किट को मंजूरी दे दी है, जो हनुमानजी एवं उनके पुत्र मकरध्वज की मूर्तियों वाला एकमात्र मंदिर है। विदित हो कि इस सर्किट के आसपास दो महत्त्वपूर्ण झीलें भी है, जिन्हें रणछोड़ तालाब और शंखुधर झील के नाम से जाना जाता है।

क्या है?

1. 21 जनवरी, 2015 को शुरू की गई हृदय योजना के

क्या है हृदय योजना?

1. केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने नेशनल हेरीटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना (HRIDYA) की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की थी।
2. इस योजना का लक्ष्य देशभर में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण तथा उनका पुनरुद्धार आदि कराना है।
3. 27 माह (मार्च 2017 में पूरा करना है) के लक्ष्य के साथ शुरू की गई इस योजना के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे।
4. इसके तहत 12 शहरों का चयन किया गया है। इनमें अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलकन्नी और वारंगल की ऐतिहासिक इमारतों का पुनर्रुद्धार किया जाएगा।
5. जिन इमारतों एवं स्थलों का जीर्णोद्धार तथा पुनरोद्धार किया जा रहा है उन इमारतों का चयन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर किया है।
6. योजना के तहत ऐतिहासिक इमारतों में जल प्रबंधन, साफ-सफाई, ड्रेनेज, कचरा प्रबंधन, सड़क मार्ग, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स, पर्यटन सुविधा केंद्र, बिजली सप्लाई जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

तहत अब तक 500 करोड़ रुपये की कुल लागत से 12 चिन्हित शहरों में धरोहरों से संबंधित बुनियादी ढाँचे के विकास का कार्य शुरू किया जा रहा है, जिनमें बेट द्वारिका भी शामिल है।

2. सभी 12 मिशन शहरों के लिये 420 करोड़ रुपये के निवेश वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

सबसे बेहतर जीवन वाले शहरों की तैयार होगी सूची

देश में कौन सा शहर सबसे बेहतर तरीके से रहने लायक है और किसकी हालत सबसे खराब है, इसकी जानकारी जल्द ही मिलने वाली है। शहरी विकास मंत्रालय ने रहने लायक बेहतर शहरों की सूची (सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स) जारी करने का फैसला किया है। इसके लिए 15 श्रेणियों में 77 मानकों पर हर शहर का आकलन होगा। पहले विभिन्न मानकों के आधार पर चार सूची संस्थागत (सरकारी), सामाजिक, आर्थिक व भौतिक सुविधाओं की बनाई जाएगी। इनके आधार पर उस शहर की श्रेणी (रैंक) तय की जाएगी।

क्या है?

1. केंद्र सरकार ने बीते ढाई साल में देश के शहरों को बेहतर बनाने के लिए अमृत, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, हृदय और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के जरिये काफी धनराशि मुहैया कराई है।
2. इन पांच प्रमुख योजनाओं में देश के सभी शहर आ जाते हैं। अब केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के आंकलन व राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा किए गए उपयोग के आधार पर शहरों की स्थिति जानेगी तथा बेहतर सुविधाओं वाले शहरों की सूची जारी करेगी।
3. इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरा ब्योरा शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को सौंप दिया है। इस पर 28 फरवरी को सभी राज्यों के साथ राष्ट्रीय कार्यशाला में विचार विमर्श होगा।

सुविधाओं का होगा आंकलन

1. शहरों में जीवन गुणवत्ता को जानने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। इनमें संस्थागत व सरकारी स्तर पर मिलने वाली सुविधाओं के लिए सिटीजन चार्टर बना है।
2. इसके मुताबिक तय समय में शिकायतों का निवारण, मिलने वाली सुविधाएं, नागरिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं, बिलों के जरिये आने वाला कर, विभिन्न सेवाओं का संचालन व रख-रखाव आदि का आकलन होगा।

चार क्षेत्रों के लिए तय किए गए अंक

1. जिन पंद्रह श्रेणियों के सूचकांक बनाए गए हैं, उनमें पहचान व संस्कृति (ऐतिहासिक भवनों के रख-रखाव, हर साल आने वाले पर्यटकों की संख्या), आर्थिक व रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सार्वजनिक व खुली जगह, भूमि उपयोग, बिजली, परिवहन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस कचरा निपटान, जनसंख्या, सुरक्षा व संरक्षा शामिल हैं।
2. इन सारे सूचकांकों को बाद में चार क्षेत्रों (सरकारी, सामाजिक, आर्थिक व भौतिक सूचकांकों) में वर्गीकृत किया जाएगा।
3. सरकारी क्षेत्र के तहत आने वाले मानकों को 30 फीसदी, सामाजिक क्षेत्र के तहत आने वाले मानकों को 20 फीसदी, आर्थिक क्षेत्र के तहत आने वाले मानकों को दस फीसदी व भौतिक व्यावहार्यता क्षेत्र के तहत आने वाले मानकों को 40 फीसदी अंक दिए जाएंगे।

इस तरह होगी शहर की रेटिंग

सभी अंकों को मिलाने पर जिसे 50 फीसदी अंक मिलेंगे, उसे शून्य, 50 से 75 फीसदी अंक वालों को .50 और 75 से 99 फीसदी अंक वालों को .75 व सौ फीसद अंक वालों को एक रैंक दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस रेटिंग के बाद शहर अपना स्तर सुधारेंगे और नागरिकों का भी दबाब बढ़ेगा। इसके साथ ही उनमें जागरुकता भी आएगी।

कैसी है ये पहल?

1. चार वर्गों, 15 श्रेणियों व 77 मानकों के आधार पर होगी हर शहर में सुविधाओं की गणना
2. केंद्र सरकार की पांच प्रमुख शहरी योजनाओं के बाद सरकार जानेगी हर शहर का स्तर

मुंबई सबसे अमीर शहर

भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई देश का सबसे अमीर शहर है। मुंबई में 46,000 करोड़पति तथा 28 अरबपति रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई की कुल संपदा 820 अरब डॉलर है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ के अनुसार मुंबई देश का सबसे अमीर शहर है। दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे पर बेंगलुरु हैं। दिल्ली में करोड़पतियों की संख्या 23,000 और अरबपतियों की 18 है। दिल्ली की कुल संपदा 450 अरब डॉलर आंकी गई है। वहीं बेंगलुरु की कुल संपदा 320 अरब डॉलर है। वहां 7,700 करोड़पति और आठ अरबपति रहते हैं।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

क्या है?

1. इस सूची में हैदराबाद 310 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर है। हैदराबाद में करोड़पतियों की संख्या 9,000 और अरबपतियों की छह है। कोलकाता में करोड़पतियों की संख्या 9,600 है और वहां 4 अरबपति रहते हैं। कोलकाता की कुल संपदा 290 अरब डॉलर आंकी गई है।
2. इस सूची में शामिल अन्य शहरों में पुणे की कुल संपदा 180 अरब डॉलर है। वहां 4,500 करोड़पति और पांच अरबपति रहते हैं। चेन्नई की संपदा 150 अरब डॉलर है। वहां 6,600 करोड़पति और चार अरबपति रहते हैं। गुड़गांव की कुल संपदा 110 अरब डॉलर है। वहां 4,000 करोड़पति और दो अरबपति निवास करते हैं।
3. इस सूची में जो अन्य उभरते शहर शामिल हैं उनमें सूरत, अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, गोवा, चंडीगढ़, जयपुर और वडोदरा शामिल हैं। देश में कुल संपदा 6,200 अरब डॉलर है। यह आंकड़ा दिसंबर, 2016 तक के हैं। देश में कुल करोड़पतियों की संख्या 2,64,000 और अरबपतियों की संख्या 95 है।
4. भारत उन पांच शीर्ष देशों में शामिल है जहां से बड़ी संख्या में करोड़पति लोग विदेश जाकर बस रहे हैं। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार बीते साल यानी 2016 में भारत से 6,000 ऐसे करोड़पति विदेश जाकर बस गए और यह संख्या इससे पूर्व वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है।
5. इसके अनुसार 2016 में लगभग 6,000 करोड़पति भारतीयों ने अपना निवास बदला जबकि 2015 में 4,000 करोड़पति विदेश जाकर बस गए थे।
6. सबसे अधिक धनी लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। लगातार दूसरे साल वह इस लिहाज से पहले स्थान पर रहा है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 11,000 करोड़पति 2016 में ऑस्ट्रेलिया जाकर बसे। इसी दौरान 10,000 करोड़पति अमेरिका व 3,000 करोड़पति ब्रिटेन गए। रिपोर्ट में करोड़पति से आशय 10 लाख डॉलर या अधिक शुद्ध संपत्ति वाले व्यक्तियों से है।

ट्रोपेक्स सैन्य युद्धाभ्यास 2017

भारतीय नौसेना ने वायुसेना और थल सेना के साथ मिलकर एक माह लंबा युद्धाभ्यास पूरा कर लिया है। द थियेटर रेडिनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज (ट्रोपेक्स) नामक इस युद्धाभ्यास में 45 जहाज और 70 विमानों ने हिस्सा लिया। देश की पश्चिमी समुद्री सीमा में यह युद्धाभ्यास 24 जनवरी से 23 फरवरी तक चला।

क्या है?

1. एक आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार इस युद्धभ्यास से भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर अपनी हमला करने की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। संघर्ष के जटिल हालात में संयुक्त अभियानों के लिए आपसी तालमेल को भी परखा गया।
2. वर्ष 2017 के ट्रोपेक्स सैन्य युद्धाभ्यास में युद्ध के विभिन्न पहलुओं का अभ्यास किया गया। दुश्मन पर हमला करने की क्षमताओं को तीनों सेनाओं ने मिलकर और धार दी। इससे पहले ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास जनवरी 2015 में किया गया था।

देश का पहला 'हेलीपोर्ट' दिल्ली में हुआ शुरू

देश का पहले हेलीपोर्ट का राजधानी दिल्ली के रोहिणी में उद्घाटन हुआ है। इस हेलीपोर्ट बनने से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बोझ कुछ कम होगा। कुल 25 एकड़ के दायरे में बने इस हेलीपोर्ट में एक साथ 10 हेलीकॉप्टर उड़ान भर या उतर सकते हैं। इस हेलीपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, उपराज्यपाल अनिल बैजल और बीजेपी सांसद उदित राज मौजूद थे। रोहिणी का हेलीपोर्ट उत्तर-भारत के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के केंद्र के रूप में काम करेगा। इस हेलीपोर्ट से पश्चिमी उत्तर-प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों के लिए उड़ान संभव होगा। यह हेलीपोर्ट वैसे तो पिछले साल ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अभी तक रात में उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिलने की वजह से इसका औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ था।

इस हेलीपोर्ट में खास

1. इस प्रोजेक्ट की लागत है 100 करोड़
2. इस प्रोजेक्ट को दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में तैयार किया गया है।
3. इस हेलीपोर्ट में बनी इमारत में एक बार में करीब 150 यात्री रूक सकते हैं।
4. इस हेलीपोर्ट में हेलीकॉप्टर को रखने के लिए करीब चार हैंगर का निर्माण भी किया गया है।
5. इन हैंगरों में एक बार में करीब 16 हेलीकॉप्टर खड़े किये जा सकेंगे।
6. इस हेलीपोर्ट को पवन हंस कंपनी संचालित करेगी।
7. यह हेलीपोर्ट रोहिणी में करीब 25 एकड़ में बना है और यह रिठाला मेट्रो स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है।
8. पिछले एक साल से इस हेलीपोर्ट का ट्रायल चल रहा था जो सफल रहा।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

अंतर्राष्ट्रीय

पाकिस्तानी संसद में हिंदू विवाह विधेयक पारित

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पाकिस्तान की संसद सीनेट ने अल्पसंख्यक हिदुओं से संबंधित विवाह विधेयक पारित कर दिया। विवाद में रहे इस विधेयक को संशोधन के बाद सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस विधेयक के पारित हो जाने से पाकिस्तान में पहली बार हिंदू अल्पसंख्यकों को पहचान मिली है और अल्पसंख्यक होने का अधिकार मिला है। इस विधेयक को संसद का निचला सदन नेशनल असेंबली 26 सितंबर, 2015 को पारित कर चुकी है। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद यह कानून में तब्दील हो जाएगा। इससे हिंदू महिलाओं के जबरन धर्मांतरण पर रोक लगेगी।

कानून के प्रमुख प्रावधान

1. 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवक व युवतियों पर लागू होगा कानून।
2. हिंदुओं के विवाह का पंजीकरण होगा।
3. विवाह विच्छेद के लिए कोर्ट में अर्जी देनी होगी।
4. विवाह के नियमों का उल्लंघन करने पर दोषी को सजा मिलेगी।
5. तलाकशुदा हिंदू महिला या पुरुष को दोबारा शादी करने की अनुमति मिलेगी।
6. पति की मृत्यु के छह महीने बाद महिला को स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार होगा।
7. इस कानून के अमल में आने के बाद मुस्लिमों में निकाहनामा की तर्ज पर पंडित शादी परथ मुहैया कराएंगे। इसके बाद संबंधित सरकारी विभाग में शादी का पंजीकरण कराया जा सकता है।

क्या है?

1. विधेयक में लड़कों और लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है। बनने वाला कानून शादी, शादी के पंजीकरण, तलाक और दोबारा शादी के मामलों पर लागू होगा।
2. इससे पाकिस्तानी हिन्दू महिलाओं को उनकी शादी का सरकारी सुबूत मिलेगा। यह हिंदू पर्सनल लॉ पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रदेशों में लागू होगा। सिंध प्रांत की विधानसभा ने खुद का हिंदू पर्सनल लॉ बनाकर उसे पहले से ही लागू किया हुआ है। डॉन न्यूज़ के अनुसार विधेयक के मसौदे का पाकिस्तान में रहने वाले ज्यादातर हिंदुओं ने समर्थन किया है।

स्पेस एक्स ने रचा इतिहास

अमेरिका में फ्लोरिडा के केप केनावेरल स्थित केनेडी स्पेस सेंटर में फॉल्कन-9 रॉकेट अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर नासा की सामग्री पहुंचाकर सुरक्षित वापस लौट आया। नासा की मदद करने वाली स्पेस-एक्स कंपनी के इस रॉकेट ने पहली बार जमीन पर स्थित लॉच पैड पर सुरक्षित लैंड किया है।

क्या है?

1. स्पेस-एक्स कंपनी के सीईओ ऐलन मस्क ने लैंडिंग की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, बेबी कम बैक। कंपनी के रॉकेट ने इससे पहले समुद्र में बने लॉच पैड पर पांच बार सुरक्षित वापसी की थी, लेकिन जमीन पर यह कारनामा पहली बार है।
2. चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग को भी इसी लांचिंग पैड एलसी-40 से भेजा गया था। वर्ष 1969 में मिशन कमांडर आर्मस्ट्रांग और पायलट बज एल्ड्रिन को अमेरिका ने चंद्र मिशन पर भेजा था।

फ्लैश पॉइंट

1. वर्तमान में भारत और यूनान के बीच कोई भी वायु संपर्क समझौता नहीं है।
2. यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (International Civil Aviation Organization & ICAO) के नए दिशानिर्देशों के अनुरूप है और इसे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क में सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
3. गौरतलब है कि नागर विमानन नीति के अनुसार भारत सरकार दक्षेस देशों और नई दिल्ली से 5,000 किलोमीटर दूर स्थित क्षेत्र वाले देशों के साथ परस्पर हित के आधार पर मुक्त आकाश करार पर दस्तखत कर सकती है।

भारत और यूनान के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी

सरकार ने यूनान द्विपक्षीय वायु सेवा करार (एएसए) पर दस्तखत को मंजूरी दे दी। इससे दोनों देशों की एयरलाइनों को एक-दूसरे के क्षेत्र में उड़ान की अनुमति मिल जाएगी। विदित हो कि भारत ने यूनान के साथ सितंबर, 2016 में 'मुक्त आकाश' करार पर दस्तखत किये थे। उससे पहले गत जून में भारत ने नई नागर विमानन नीति पेश की थी। फिलहाल भारत और दक्षिणपूर्व यूरोपीय देश यूनान के बीच किसी तरह का वायु संपर्क नहीं है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

क्या है?

1. दोनों देशों की नामित विमानन कंपनीयों को एक-दूसरे देश के परिक्षेत्र में अपना कार्यालय खोलने का अधिकार होगा ताकि वह अपनी हवाई सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा दे सके।
2. दोनों देशों की नामित विमानन कंपनियों को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमति के साथ सेवाओं के संचालन के लिये उचित एवं समान अवसर उपलब्ध होंगे।
3. प्रत्येउक पक्ष की नामित विमानन कंपनी को समान पक्ष, अन्य पक्ष एवं तीसरे देश की नामित विमानन कंपनियों के साथ सहायक विपणन व्यववस्था करने का अधिकार होगा।

भारत-पाक का परमाणु हथियार समझौता बढ़ा

भारत और पाकिस्तान ने उस समझौते को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है, जो परमाणु हथियारों से जुड़े हादसों का खतरा कम करने के लिए किया गया था। समझौते के तहत दोनों देश अपने क्षेत्र में परमाणु हथियार से हादसा होने पर दूसरे को सूचना देंगे, क्योंकि विकिरण के कारण सीमापार भी नुकसान हो सकता है। इस स्थिति में विदेश सचिवों के हॉटलाइन, डिप्लोमैटिक लिंक या और किसी भी चौनल का इस्तेमाल किया जाएगा। एक दूसरे की सहमति के बिना तीसरे पक्ष को सूचना देने पर भी रोक का प्रावधान है।

क्या है?

1. समझौता पहली बार 2007 में किया गया था, जिसे 2012 में भी विस्तार दिया गया था। तब का समझौता 20 फरवरी 2017 तक के लिए लागू था। पहली बार समझौता होने से पहले तीन साल तक बातचीत चली थी। इस समझौते ने मुंबई अटैक से लेकर पठानकोट और उड़ी अटैक देखे, लेकिन यह बना रहा।
2. तनाव के बावजूद दोनों देशों ने 1988 में समझौता किया था कि वे एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे।
3. परमाणु ठिकानों की सूची सौंपने पर भी सहमति बनी और 1992 से दोनों देश हर साल सूची सौंप रहे हैं।

भारत-इजरायल मिलकर बनाएंगे मिसाइल

मोदी सरकार ने सेना के लिए इजरायल के साथ सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम श्रेणी की मिसाइल (एमआरएसएएम) संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए 17000 करोड़ रूपये के सौदे को हरी झंडी दे दी है। यह भारत का इजरायल के साथ तेजी से बढ़ते रक्षा संबंधों को प्रतिबिंबित करता है।

क्या है?

1. परियोजना को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और इजरायली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री (आईएआई) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
2. सौदे को मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वर्ष बाद में इजरायल की संभावित यात्रा से पहले दी गयी है। 2017 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापना की 25वीं वर्षगांठ है।
3. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की गत बुधवार को हुई बैठक में मिसाइल सौदे को मंजूरी प्रदान कर दी गई।
4. एमआरएसएएम नौसेना के लिये सतह से हवा में मार करने वाली लंबी श्रेणी की मिसाइल (एलआरएसएएम) का भूमि आधारित संस्करण है, जिसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक होगी।

ऑरियन के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना

अमेरिका की स्पौस एजेंसी नासा अंतरिक्ष यात्रियों को आगामी मिशन के तहत सुदूर अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रही है। नासा की योजना स्पे स कैपसूल ऑरियन के जरिए चंद्रमा के ऑर्बिट में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की है, हालांकि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

क्या है?

1. नासा की योजना के तहत वर्ष 2030 में इस कैपसूल के माध्यम से अंतरिक्ष यात्री सफल और सुरक्षित तरीके से अंतरिक्ष में घूम सकेंगे। अभी तक इस मिशन को एक्सेप्लोमरेशन मिशन 1 के नाम से ही जाना जा रहा है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

2. वर्ष 2018 में नासा की योजना ऑरियन को टेस्टि फ्लाइट पर भेजने की है। यह मानवरहित मिशन होगा। नासा के प्रशासक रोबर्ट लाइटफुट का कहना है कि नासा आने वाले समय में इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की है, इस बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। जल्द ही इस पर फैसला भी कर लिया जाएगा।
3. नासा इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देना चाहता है। उनके मुताबिक ऑरियन को अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्ट म के तहत भेजा जाएगा। यह रॉकेट खासतौर पर इसी तरह के मिशन के लिए बनाया गया है। ऑरियन की खासियत है कि यह अंतर्क्षि में इंसान को लेकर काफी दूर तक जा सकता है और सुरक्षित वापस भी आ सकता है।
4. इतना ही नहीं यह बिना किसी स्पेस स्टेशन से जुड़े लंबे समय तक अंतरिक्ष में बने रह सकता है। नासा इस 2019 में होने वाले मिशन को लेकर क्रू मैंबर्स का नाम अंतिम करने में लगा हुआ है।
5. नासा की योजना वर्ष 2021 में ऑरियन को आठ दिन के अंघ्तरिक्ष मिशन पर भेजने की भी है।

स्लोवेनिया में समलैंगिक विवाह को मंजूरी

मध्य यूरोपीय देश स्लोवेनिया ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है। हालांकि ऐसे जोड़े को बच्चे गोद लेने की अनुमति नहीं होगी। स्लोवेनिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मारिबोर के अधिकारी सेंजिया क्लैंपफर ने बताया कि यहां पहला समलैंगिक विवाह होगा। उन्होंने कहा, 'हम प्रसन्न हैं और हमें इस फैसले पर गर्व है। हमारा मानना है कि इस कदम से ऐसा समावेशी समाज बनाने में सहायता मिलेगी, जहां सभी को बराबर अधिकार हों।' ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसे कुछ देश पहले ही समलैंगिक विवाह हो मंजूरी दे चुके हैं। वहीं कई यूरोपीय देशों में अब भी इस पर बहस चल रही है। समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता लाना गोबेक ने कहा कि यह बड़ा कदम है। हम समलैंगिकों को संपूर्ण अधिकार मिलने तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्हें बच्चे गोद लेने और कृत्रिम तरीकों से माता-पिता बनने जैसे अधिकार भी मिलने चाहिए।

भारत और रवांडा के बीच तीन समझौतों पर हस्ताक्षर

उपराष्ट्रपति हामिद हंसारी की रवांडा यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत-रवांडा के बीच तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। भारत और रवांडा ने नवोन्मेष, उड्डयन क्षेत्रों एवं वीजा जरूरत से जुड़े तीन सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए।

क्या है?

1. नवोन्मेष क्षेत्र में दोनों देश किगाली में एक उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना करेंगे जबकि उड्डयन क्षेत्र में रवांडा एयर आने वाले महीनों में भारत के लिए सेवाएं शुरू करेगी और दोनों देश राजनयिक एवं आधिकारिक पासपोर्ट धारकों की वीजा जरूरत को पारस्परिक तरीके से छूट देंगे।
2. रवांडा के प्रधानमंत्री अनस्तासे मुरेकेजी ने कहा कि इन सहमति पत्रों से आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, 'रवांडा एवं भारत के बीच 54 साल का महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है और हम इस मजबूत संबंध के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3. अंसारी रवांडा और युगांडा के पांच दिवसीय यात्रा पर हैं। अंसारी के साथ पत्नी सलमा अंसारी और सरकारी और निजी क्षेत्र के अधिकारियों की एक 27 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है।

पाकिस्तान में टेस्ट ट्यूब बेबी को मान्यता

इस्लामी कानून लागू करने वाली पाकिस्तान की शरई अदालत ने बेऔलाद औरत-मर्द के हक में प्रगतिवादी फैसला सुनाया है। शादीशुदा जोड़े अब टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद से मां-बाप बन सकते हैं। मां-बाप बनने का यह तरीका पूरी तरह से कानूनी होगा।

क्या है?

1. देश की संघीय शरई अदालत ने सुनाए फैसले में कहा, पिता और माता के जनन द्रव्य का टेस्ट ट्यूब में निषेचन हो और उसके बाद तैयार भ्रुण वापस मां की कोख में प्रतिस्थापित किया जाए।
2. इस प्रक्रिया से पैदा होने वाला बच्चा पूरी तरह से कानून सम्मत होगा। 22 पन्नों के फैसले में अदालत ने कहा है कि संतान पैदा करने का यह तरीका कुरान के किसी प्रावधान के खिलाफ नहीं है। क्योंकि होने वाली संतान उन्हीं मां-बाप की होगी, जिसका नाम उसे पैदा होने के बाद मिलेगा।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

3. मां-बाप की सेहत की पेचीदगियों के चलते बच्चे की पैदाइश के लिए सिर्फ मेडिकल साइंस का सहारा लेना गलत नहीं होगा।
4. फैसले में साफ किया गया है कि इसके अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबी को लेना या उसे पैदा करना गैर इस्लामिक होगा। किराये की कोख लेकर व बच्चा पैदा करने के अन्य तरीके इस्लाम के खिलाफ माने जाएंगे।

आर्थिक

आर्थिक आजादी सालाना सूचकांक

आर्थिक आजादी संबंधी सालाना सूचकांक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। पिछले साल के 123 वें स्थान से खिसकर यह 143वें स्थान पर आ गया है। अमेरिकी शोध संस्थान 'द हेरिटेज फाउंडेशन' की 'इंडेक्स ऑफ इकनॉमिक फ्रीडम' रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समेत कई दक्षिण एशियाई देशों से कम है।

क्या है

1. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पिछले 5 वर्षो के दौरान औसतन 7 प्रतिशत की दर से आर्थिक तरक्की हुई है, लेकिन यह वृद्धि नीतियों में गहरे तक नहीं समाई, जिससे आर्थिक आजादी की रक्षा की जा सके। भारत की कमजोर स्थिति को परंपरागत राजनीतिक विचारधारा का नतीजा करार दिया गया है।
2. रिपोर्ट में भारत को 'अधिकांशत: गैर--खुली' अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि यहां बाजार आधारित सुधारों से हुई प्रगति असमान रही है।
3. हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड अव्वल भारत ने कुल 52.6 अंक हासिल किए, जो पिछले साल के मुकाबले 3.6 अंक कम हैं।
4. सूचकांक में हांगकांग, सिंगापुर और न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहे। भारत से नीचे अफगानिस्तान 163वें और मालदीव 157वें स्थान पर हैं।
5. नेपाल का स्थान 125वां, श्रीलंका का 112वां, पाकिस्तान का 141वां, भूटान का 107वां और बांग्लादेश का 128वां है। अमेरिका 17 वें और चीन 111वें स्थान पर है।

जीएसटी मॉडल कानून का मसौदा तैयार

बहु-प्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर एक जुलाई 2017 से लागू होने की दिशा में एक और अहम पड़ाव पार होने वाला है। जीएसटी मॉडल कानून के मसौदे पर कानून मंत्रालय ने मुहर लगा दी है और जीएसटी काउंसिल 4-5 मार्च को होने वाली बैठक में इसे अंतिम रूप दे देगी। इसके बाद सरकार केंद्रीय जीएसटी के विधेयक को 9 मार्च से शुरु हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश कर पारित कराने का प्रयास करेगी। वहीं राज्य भी अपनी-अपनी विधान सभा में राज्य जीएसटी विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया शुरु कर सकेंगे।

क्या है?

1. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की 11वीं बैठक में जीएसटी मॉडल कानून के पूर्ण मसौदे को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कानून मंत्रालय इसे कानूनी कसौटी पर परख चुका है।
2. कानून मंत्रालय ने 11 फरवरी को जीएसटी मॉडल कानून को पहली बार कानूनी कसौटी पर परखा, उसके बाद 13 फरवरी से फिर यह प्रक्रिया दोहरायी गयी। इस दौरान पूरा जोर इस बात पर रहा कि जीएसटी मॉडल कानून के प्रस्तावित प्रावधान कानून सम्मत हैं या नहीं।
3. यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक जीएसटी काउंसिल की बैठकों में जीएसटी के सिर्फ निश्चित प्रावधानों पर ही चर्चा होती थी, आगामी बैठक में इस पर समग्रता से विचार किया जाएगा।
4. सरकार ने 26 नवंबर 2016 को जीएसटी कानून का संशोधित मसौदा जनता की प्रतिक्रिया के लिए रखा था। इसके बाद जीएसटी काउंसिल के सचिवालय ने इसमें कई सुधार किए हैं।
5. जीएसटी काउंसिल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार इस मॉडल कानून को संसद से मंजूरी दिलाएगी। केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी कानूनों के प्रावधान समान होंगे इसलिए काउंसिल जिस मॉडल विधेयक के मसौदे को मंजूरी देगी, उसे ही राज्य विधानसभाएं मंजूरी दे देंगी
6. गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की उदयपुर में हुई 10वीं बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल जैसे अहम प्रावधानों को मंजूरी दी गयी थी। हालांकि कुछ बिन्दुओं पर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पायी थी जिसके चलते जीएसटी मॉडल कानून के मसौदे को अगली बैठक में रखने का फैसला किया गया था।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

विज्ञान और तकनिकी

सरकार ने शुरू किया साइबर स्वच्छता केंद्र

डिजिटल इंडिया में साइबर सुरक्षा की दिशा में बड़ी पहल करते हुए केंद्र सरकार ने देश में एक साइबर स्वच्छता केंद्र की शुरुआत की है। यह केंद्र लोगों के पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल फोन जैसे उपकरणों को वायरस और नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयरों से बचाव के लिए एंटी वायरस उपलब्ध कराएगा।

क्या है?

1. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से स्थापित इस एंटी मालवेयर एनालिसिस सेंटर लोगों को मुफ्त एंटी वायरस उपलब्ध कराएगा।
2. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। इसे 90 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इस मौके पर प्रसाद ने कहा कि सभी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों से कहा गया है कि वे अपने ग्राहकों को इस मंच पर आने के लिए प्रेरित करें। सरकार ने इस केंद्र को साइबर स्वच्छता केंद्र का नाम दिया है।
3. इस केंद्र के जरिए कंप्यूटर एमर्जेसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) वायरस के हमले से पीड़ित सिस्टम से सारी जानकारी लेकर इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों और बैंकों को उपलब्ध कराएगी। इसके बाद इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां और बैंक अपने ग्राहकों को उनके पीसी या मोबाइल में गड़बड़ी के बारे में सतर्क करेंगे और उस मलबेयर को दूर करने के लिए बोटनेट की वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की सिफारिश करेंगे। ग्राहकों को ये सॉफ्टवेयर मुफ्त में डाउनलोड कर सकेंगे।
4. अब तक 58 इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां और 13 बैंक इस केंद्र के साथ जुड़ चुके हैं। प्रसाद ने सीईआरटी-इन को जून से पहले नेशनल साइबर कोआर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने को कहा है। सरकार ने इस सेंटर के लिए 900 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं।
5. इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला ने प्रसाद से मुलाकात की। प्रसाद ने नाडेला से सरकार के डिजिगांव कार्यक्रम से जुड़कर उसमें योगदान करने का आग्रह किया। डिजिगांव डिजिटल अभियान का एक अभिन्न हिस्सा है। प्रसाद ने बाद में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की।

दुनिया का पहला 5G स्मार्टफोन

बर्सिलोना में हो रहे मोबाइल वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस में ZTE कंपनी ने दुनिया का पहला 5जी स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह 5जी नेटवर्क को सपोर्ट करता है जो नेटवर्क 2020 तक आ सकता है। कंपनी ने इस फोन के बारे में कहा कि शगिगाबाइट फोनश दुनिया का पहला ऐसा फोन है जिसकी डाउनलोडिंग स्पीड 1 जीबी प्रति सेकेंड तक होगी।

क्या है?

1. कंपनी के मुताबिक ZTE का यह गिगाबाइट स्मार्टफोन है जिसमें 1GBPS की डाउनलोडिंग स्पीड है। यह 4ळ की पहली जनरेशन से 10 गुना फास्ट है। ऐसे में इस स्पीड से एक पूरी मूवी महज एक सेकेंड में डाउनलोड की जा सकती है।
2. इस फोन में क्वॉलकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर होगा। टेक कंपनियां 5जी यानी पांचवे जेनेरेशन के नेटवर्क को सपोर्ट करने वाली डिवाइस बनाने में लगी हैं। ताकि आने वाले समय में लोग अपने स्मार्टफोन पर ही फिल्म और टीवी देख सकें। साउथ कोरियन कैरियर KT Corp का लक्ष्य Pyeongchang में होने वाले विंटर ओलंपिक 2018 में 5G नेटवर्क का ट्रायल करना है।
3. चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी ZTE ने स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित MWC 2017 में दुनिया का पहला 5जी स्मार्टफोन लॉन्च किया है। गिगाबाइट फोन 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है।
4. कंपनी के मुताबिक यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें सुपर स्पीड वाले 5G नेटवर्क का सपोर्ट दिया गया है। हालांकि फिलहाल 5जी नेटवर्क 2020 तक आने की संभावना है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

टेनिस सिखाने वाला पहला रोबोट

वर्तमान समय में खेल क्षेत्र में ऐसे कई रोबोट हैं, जिसने खिलाड़ियों को सीखने में मदद मिलती है। बेस बॉल, फुटबॉल और क्रिकेट में इनके सहारे खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, खेल से संबंधित खिलाड़ियों को कई बार बारीकियां भी सीखने को मिलती है। लेकिन जापान का एक रोबोट इन सबसे आगे निकल गया है। टेबल टेनिस में खिलाड़ियों को बेहद ही क्विक स्मैस की जरूरत होती है और इसके लिए यह रोबोट मददगार होगा।

रोबोट में क्या है खास?

1. इसमें तीन कैमरे लगे हैं।
2. यह टेबल टेनिस की गेंद को त्रि-आयामी तस्वीरों के रूप में देखते हैं।
3. साथ ही खेलने वाले व्यक्ति की गतिविधियों या शॉट पर भी पैनी नजर रखता है।
4. कंप्यूटर की मदद से रोबोट गेंद की गति और उसके गिरने का स्थान का सटीक आंकलन करता है।
5. इससे फॉरफ्यूरस को रैकेट से गेंद मारने का सटीक निर्देश मिलता है।
6. यह भुजा या कंप्यूटर ब्रेन से निर्देश मिलने पर तेजी से प्रतिक्रिया देती है। इसी में लगे रैकेट से रोबोट गेंद मारता है।
7. टेबल के बीच में लगे इस जाली पर ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रोबोट के विचार और खेल से जुड़ी अन्य जानकारी फ्लैश होती रहती है।
8. ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए व्यक्ति की खेल रणनीति और गेंद का रास्ता पहचानता है।

क्या है?

1. टेबल टेनिस सिखाने वाला 'फॉरफियुअस' नाम का दुनिया का यह पहला रोबोट है। जापानी कंपनी के मुताबिक नए टेक्नोलॉजी में कोई भी अन्य खेल का रोबोट बेहतर नहीं होगा। इस रोबोट का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है।
2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फॉरफियुअस रोबोट लोगों बड़ी आसानी से टेबल टेनिस सिखा रहा है।
3. रोबोट का पूरा नाम 'फ्यूचर ऑमरोन रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी फॉर एक्सप्लोरिंग पॉजिबिलिटी ऑफ हार्मोनाइज्ड ऑटोमेशन विद सिनिक थियोरेटिक्स' (फॉरफियुअस) है।
4. इस रोबोट को जापानी कंपनी ऑमरोन कॉपरेशन ने बनाया है। कंपनी के वैज्ञानिक ताकू ओया ने 2013 में इस रोबोट को तैयार किया था।

NASA ने खोजे धरती जैसे 7 ग्रह

खगोल वैज्ञानिकों ने एक ही तारे की परिक्रमा करते धरती के आकार के कम-से-कम सात ग्रहों को खोज निकाला है। मीडिया को जानकारी देते हुए विज्ञानियों ने कहा कि पहली बार धरती के आकार जैसे सात नए ग्रहों की खोज की गई है जहां जीवन की संभावना है। ये ग्रह 39 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा कर रहे हैं।

क्या है?

1. विज्ञान पत्रिका नेचर में बेल्जियम स्थित लिएजे यूनिवर्सिटी के अग्रणी अनुसंधानकर्ता माइकल गिलोन के हवाले से कहा गया, वहां कुछ तरल पानी हो सकता है और जीवन हो सकता है।
2. नासा ने इसे नया रिकॉर्ड करार देते हुए कहा कि स्पिट्जर स्पेहस टेलीस्कोप ने पाया कि ये ग्रह आकार में पृथ्वी जितने बड़े हैं और आवासीय जोन के दायरे में आते हैं।
3. खगोल विज्ञानी पहले भी सात अन्य ग्रहों की खोज कर चुके हैं, लेकिन यह पहली बार है जब धरती के आकार जैसे इतने सारे ग्रह मिले हैं। वे सभी सही दूरी पर परिक्रमा करते हैं और संभवत: उनकी सतह पर कहीं न कहीं तरल पानी है।
4. नासा ने बताया कि उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नए सोलर सिस्टम की खोज की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इनमें से एक ग्रह बिल्कुल पृथ्वी जैसे हालात पेश कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहला मौका है जब सभी प्लेनेट एक स्टार के आस-पास मौजूद हैं।
5. वैज्ञानिकों के मुताबिक स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप जैसे रिजल्ट इस बार आए ये बेहद चौंकाने वाले हैं। इससे पहले इस तरह के रिजल्ट कभी नहीं देखे गए। फिलहाल की नजरें इस नए प्लेनेट में पानी की तलाश करने पर है। अगर यहां पानी मिलता है तो जीवन की संभावना बढ़ सकती है।
6. आज यानी 23 फरवरी को गूगल ने एक बहुत ही क्रिएटिव डूडल बनाया है। ये डूडल नासा की नई सुखद खोज पर बनाया गया है। डूडल में पृथ्वी और चंद्रमा टेलीस्कोप से आकाश में देख रहे हैं, तभी उन्हें एक ही सूर्य के ऑर्बिट में 7 ग्रह दिख जाते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा अपनी इस खोज पर बहुत खुश हैं।

जेम्स वेब्ब स्पेस टेलिस्कोप

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope - JWST) विश्व की सर्वाधिक उन्नत अंतरिक्ष वेधशाला (Advanced Space Observatory) है। इस इंजीनियरिंग चमत्कार को ब्रह्माण्ड के कुछ बड़े रहस्यों को सुलझाने के उद्देश्य से

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

निर्मित किया गया है। वस्तुत: इसे बिग बैंग के पश्चात् बनने वाले प्रथम तारों और आकाशगंगाओं की खोज करने तथा तारों के चारों ओर के ग्रहों के परिवेश का अध्ययन करने संबंधी कार्य करने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है। इस वेब के प्रक्षेपण की घोषणा करने से पहले, इससे संबद्ध इंजीनियरों और तकनीशियनों द्वारा इस मिशन के सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है ताकि असफलता की कोई गुंजाईश न रहे।

क्या है?

1. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (जिसे जेडब्ल्यूएसटी अथवा वेब भी कहा जाता है) अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी टेलिस्कोप होगी।
2. इसका नामकरण नासा विज्ञान मिशनों के दूसरे व्यवस्थापक तथा चौंपियन जेम्स वेब के नाम पर किया गया है।
3. इससे पूर्व जेडब्ल्यूएसटी (JWST) को एनजीएसटी (New Generation Space Telescope - NGST) के नाम से जाना जाता था, परन्तु सितम्बर 2002 में इसका नाम बदलकर नासा के पूर्व व्यवस्थापक जेम्स वेब के नाम पर कर दिया गया।
4. इस टेलीस्कोप को वर्ष 2018 के अक्तूबर में फ्रेंच गुयाना से यूरोप के एरिन 5 प्रक्षेपास्त्र के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगाप
5. यह 6.5 मीटर प्राथमिक दर्पण युक्त एक बड़ा अवरक्त टेलीस्कोप होगाद्य जिसमें 22 मीटर (72 फीट, टेनिस कोर्ट के आकार की) की लम्बाई वाले सनशील्ड (Sunshield) और 6.5 मीटर (21 फीट) चौड़ाई के दर्पण संबद्ध होंगे।
6. जेडब्ल्यूएसटी को पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर (930,000 मील) की दूरी तक पहुँचने में एक माह का समय लगेगाद्य इस स्थिति को लेगरेंज बिंदु 2 (Lagrange Point 2) अथवा L 2 कहा जाता है।
7. इस टेलिस्कोप के माध्यम से यूरोपीय अन्तरिक्ष एजेंसी (European Space Agency) और केनेडियन अंतरिक्ष एजेंसी (Canadian Space Agency) दृश्य जगत के किनारों का पता लगाने में सक्षम हो जाएंगी।
8. सम्भवत: इस टेलिस्कोप की सफलता के पश्चात् सम्पूर्ण विश्व के वैज्ञानिक आगामी कई वर्षों तक इस वेब टेलिस्कोप के माध्यम से अंतरिक्ष के विषय में सूचनाएँ एकत्रित करने में सक्षम हो जाएंगे।

दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ड्रोन

टेक्नोलॉजी के मामले में चीन के विकास की रफ्तार अब कई विकसित देशों को पीछे छोड़ रही है। चीन ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोलर ड्रोन बनाकर इस तथ्य को सच साबित कर दिया है। सौर ऊर्जा से संचालित अपने सबसे बड़े सोलर ड्रोन का परीक्षण चीन जल्द ही कर सकता है।

सोलर ड्रोन की खास बातेः

1. चीन का यह नव निर्मित सोलर ड्रोन अब जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े सोलर ड्रोन की सूची में दूसरे पायदान आ जाएगा। चीन के एकेडमी ऑफ एयरोस्पेस एयरोडायनेमिक (सीएएए) के ड्रोन प्रोजेक्ट चीफ इंजीनियर शी वेन ने इस नए ड्रोन के बारे में जानकारी दी है।
2. इस सोलर ड्रोन के पंखों की लंबाई 40 मीटर से भी ज्यादा है। यह लंबाई चीन के प्रसिद्ध यात्री विमान बोइंग 737 से भी अधिक है। बोइंग के पंखों की कुल लंबाई 34 मीटर है, यानी सोलर ड्रोन के पंख बोइंग के पंखों से 6 मीटर ज्यादा लंबे हैं। न का यह नव निर्मित सोलर ड्रोन अब जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े सोलर ड्रोन की सूची में दूसरे पायदान आ जाएगा।
3. चीन के एकेडमी ऑफ एयरोस्पेस एयरोडायनेमिक (सीएएए) के ड्रोन प्रोजेक्ट चीफ इंजीनियर शी वेन ने इस नए ड्रोन के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस सोलर ड्रोन के पंखों की लंबाई 40 मीटर से भी ज्यादा है। यह लंबाई चीन के प्रसिद्ध यात्री विमान बोइंग 737 से भी अधिक है।
4. सोलर ड्रोन के पंख बोइंग के पंखों से 6 मीटर ज्यादा लंबे हैं। 2020 तक चीनी सेना को दिया जाएगा ड्रोन चीन द्वारा निर्मित सोलर ड्रोन अत्यधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ने में सक्षम है। वैसे तो इस तरह के ड्रोन 20 से 30 किमी की सीमित ऊंचाई तक ही पहुंचने में सक्षम होते हैं, लेकिन यह ड्रोन सामान्य से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है।

विविध

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

भारत ही नहीं, विश्व में अंग्रेजी और कुछ दूसरी भाषाओं के बढ़ते वर्चस्व के कारण मातृभाषाओं और बोलियों का दायरा सिमटता जा रहा है। ऐसी स्थिति तब है जब भाषा विज्ञानी और शिक्षाविद साबित कर चुके हैं कि मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने से बच्चा तेजी से सीखता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज में प्राध्यापक डॉ. गंगा सहाय मीणा का

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

कहना है कि यह चिंता की बात है कि मातृभाषा व बोलियां भारत में ही नहीं, विश्व में भी सिमट रही हैं। भूमंडलीकरण का एक बड़ा असर भाषाओं पर भी पड़ा है। वडोदरा के भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर के सर्वे में यह तथ्य सामने आए हैं कि पिछले पांच दशकों में भारत में बोली जाने वाली 220 से अधिक बोलियां गायब हो गई हैं।

क्या है?

1. 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1100 से अधिक भाषाएं थीं, जिनकी संख्या अब 880 से भी कम रह गई हैं।
2. यूनेस्को द्वारा बनाए गए इंटरेक्टिव एटलस में दुनिया की लगभग छह हजार भाषाओं में से 2471 खतरे में हैं। इस मानचित्रावली के अनुसार भारत की कुल 197 भाषा व बोलियां खतरे में हैं। इनमें से 81 लुप्त होने के कगार पर हैं, 63 पर लुप्त होने का गंभीर खतरा है, छह बहुत गंभीर खतरे में हैं, 42 लुप्तप्राय हैं और पांच भाषाएं हाल ही में लुप्त हो चुकी हैं।
3. जो भाषाएं हाल ही में लुप्त हुई हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं, उनको बोलने वाले समुदाय भी लुप्त हो रहे हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय और राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के निदेशक प्रो. रवि टेकचंदानी का कहना है कि भारतीय भाषाओं को पछाड़ने के लिए अंग्रेजी क्यों माध्यम बने, कोई भारतीय भाषा क्यों नहीं। यदि संस्कृत, गुजराती या सिंधी पढ़ानी हो तो किसी भारतीय भाषा में क्यों न पढ़ाया जाए। इससे मातृभाषाओं का संरक्षण होगा।
4. दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रो. मोहन का कहना है कि हिंदी के साथ जुड़कर अन्य भाषाएं समृद्ध हुई हैं। इसलिए मनाया जाता है विश्व मातृभाषा दिवस।
5. विश्व में संस्कृति व भाषाई विविधता तथा बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी को विश्वभर में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है।
6. इसकी प्रथम घोषणा 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा औपचारिक रूप से प्रस्ताव पारित कर 2008 में इसे मान्यता दी गई।

सर्च इंजन कानून का सम्मान नहीं करती हैं: सुप्रीम कोर्ट

लड़कियों की घटती संख्या मानव जाति के लिए घातक संकेत है। यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग जांच से जड़ी सामग्री पर सर्च इंजनों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने तीनों कंपनियों से ऐसी सामग्री की पहचान करने और उसे हटाने के लिए आंतरिक व्यवस्था बनाने को कहा।

क्या है?

1. घटते लिंगानुपात पर चिंता जाहिर करते हुए हालांकि कोर्ट ने तीनों कंपनियों से कहा कि वह उनके खिलाफ कोई अवमानना कार्रवाई शुरू नहीं करेगी। वह सिर्फ इतना चाहती है कि तीनों कंपनियां लिंग जांच को प्रतिबंधित करने से जुड़े कानूनों के प्रति जवाबदेह बनें।
2. कोर्ट ने कई सर्च की--वर्ड ब्लॉक करने को भी कहा था लेकिन सॉलिसीटर जनरल रंजीत कुमार ने शिकायत की कि इंटरनेट कंपनियां कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं।
3. कंपनियों ने कहा--मानते हैं निर्देश गूगल इंडिया ने कहा कि वह कोर्ट के निर्देशों का पालन करती है। अपने बयान में गूगल ने कहा कि लिंग जांच से जुड़े विज्ञापनों को हटाने के कोर्ट के निर्देश का पालन किया गया है। गूगल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि पहले ही काफी आपत्तिजनक सामग्री हटाई जा चुकी है। बाकी कंपनियों ने भी कहा कि वे भारत के कानूनों का सम्मान करती हैं। कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन करने के कोशिश की जा रही है।
4. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 11 अप्रैल तय की है। सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता साबू मैथ्यू जॉर्ज ने इस मसले पर जनहित याचिका दाखिल कर रखी है। याचिका में कहा गया है कि भारत में गर्भ में बच्चे के लिंग जांच की मनाही है। इसके बावजूद इंटरनेट पर तमाम ऐसे विज्ञापन और सामग्री मौजूद हैं, जिनमें लोगों को भ्रुण के लिंग जांच की सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

वायु प्रदूषण से हर मिनट मरते हैं दो भारतीय

जिस हवा में भारतीय सांस लेते हैं, वह दिन-प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है और एक नए अध्ययन में कहा गया है कि वायु प्रदूषण के कारण प्रतिदिन औसतन दो भारतीय मारे जाते हैं। चिकित्सीय पत्रिका द लांसेट के अनुसार, हर साल वायु प्रदूषण के कारण 10 लाख से ज्यादा भारतीय मारे जाते हैं और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से कुछ शहर भारत में हैं। यह अध्ययन वर्ष 2010 के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि वैश्विक तौर पर 27.34 लाख समय पूर्व जन्म के मामलों को पीएम 2.5 के प्रभाव से जोड़ा जा सकता है और इन मामलों में सबसे बुरी तरह दक्षिण एशिया प्रभावित होता है। यहां 16 लाख जन्म समय पूर्व होते हैं।

क्या है?

1. अध्ययन में कहा गया है कि वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्तत तौर पर एक-दूसरे से जुड़े हैं और इनसे एक साथ निपटे जाने की जरूरत है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

2. जलवायु परिवर्तन मानवीय स्वास्थ्य पर तो भारी खतरा पैदा करता ही है साथ ही साथ यदि सही कदम उठाए जाएं तो वह 21वीं सदी का सबसे बड़ा वैश्विक स्वास्थ्य अवसर भी है।
3. हर मिनट भारत में दो जिंदगियां वायु प्रदूषण के कारण चली जाती हैं। इसके अलावा, विश्व बैंक के आकलन के मुताबिक यदि भारत में श्रम से होने वाली आय के क्रम में देखा जाए तो इससे 38 अरब डॉलर का नुकसान होता है।
4. अध्ययन कहता है कि वायु प्रदूषण सभी प्रदूषणों का सबसे घातक रूप बनकर उभरा है। दुनियाभर में समय से पूर्व होने वाली मौतों के क्रम में यह चौथा सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है।
5. हाल ही में 48 प्रमुख वैज्ञानिकों ने अध्ययन जारी किया और पाया कि पीएम 2.5 के स्तर या सूक्ष्म कणमय पदार्थ (फाइन पार्टिक्युलेट मैटर) के संदर्भ में पटना और नयी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर हैं। ये कण दिल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।
6. एक आकलन के मुताबिक वायु प्रदूषण की चपेट में आने पर हर दिन 18 हजार लोग मारे जाते हैं। इस तरह यह स्वास्थ्य पर मंडराने वाला दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा पयार्वरणीय खतरा बन गया है।
7. विश्व बैंक का आकलन है कि यह श्रम के कारण होने वाली आय के नुकसान के क्रम में वैश्विक अर्थव्यवस्था को 225 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाता है।
8. कई भारतीय रिपोर्टों से विरोधाभास रखते हुए द लांसेट ने कहा कि कोयले से संचालित होने वाले बिजली संयंत्र वायु प्रदूषण में 50 प्रतिशत का योगदान देते हैं।

SC के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर का निधन

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे अल्तमस कबीर का निधन हो गया है। कोलकाता के अपोलो अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। वे डायबिटीज समेत कई बीमारियों से पीड़ित थे। अल्तमस कबीर को कई हाई प्रोफाइल केस में अहम फैसले सुनाने के लिए जाना जाता है।जस्टिस अल्तमस कबीर ने मानवाधिकार और इलेक्शन के कानूनी मुद्दों में अहम रोल अदा किया है।

क्या है?

1. जस्टिस अल्तमस का सबसे अहम केस वर्ष 2011 में महाराष्ट्र की अमरावती जिले के संध्या मनोज वानखेडे को लेकर था। अल्तमस के पिता जहांगीर कबीर कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे। जो कि बंगाल में ट्रेड यूनियन के भी नेता थे। उन्होंने बंगाल में मंत्री पद की भी जिम्मेदारी निभाया है। साथ ही उन्हें पहली गैर कांग्रेसी सरकार में वर्ष 1967 में मंत्री बनने का मौका मिला।
2. अल्तमस कबीर ने पिता के इतर वकालत को अपना पेशा चुना। उन्होंने एक वकील के रुप में अपना करियर वर्ष 1973 में शुरु किया। जिला न्यायालय और हाईकोर्ट में बतौर वकील कई वर्षों तक अल्मस कबीर ने प्रैक्टिस की।
3. वर्ष 1990 में अल्तमस कबीर को कलकत्ता हाईकोर्ट का जज बनाया गया। मार्च 2005 में उन्हें झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का गौरव प्राप्त हुआ।
4. सितंबर 2012 में अल्तमस कबीर सुप्रीम कोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश बने। जहां 18 जुलाई 2013 तक वो बतौर मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रहे। जिनके बाद पी सतशिवम देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बने।

कृषि योग्य भूमि का विकल्प हो सकती है वर्टिकल खेती

आबादी बढ़ने के साथ कम होती कृषि योग्य भूमि को देखते हुए जयपुर में वर्टिकल खेती (खड़ी खेती) का सफल प्रयोग किया जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता यानि उत्पादन पूरी तरह आर्गेनिक है।

क्या है?

1. जयपुर स्थित सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय में पिछले एक साल से वर्टिकल खेती पर रिसर्च हो रही है और परिणाम बहुत ही सकारात्मक आए हैं। इस शोध के बाद आम लोग अपनी छतों पर भी अपने उपयोग लायक सब्जियां पैदा कर सकेंगे। इसके लिए न तो मिट्टी की जरूरत होगी और न तेज धूप की।
2. विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के शोधार्थी कृषि विज्ञानी अभिषेक शर्मा के मार्गदर्शन में यह प्रयोग कर रहे हैं। यहां टमाटर, चिली, कॉली फ्लावर, ब्रोकली, चीनी कैबेज, पोकचाई, बेसिल, रेड कैबेज का उत्पादन किया जा रहा है।

क्या है ये तकनीक

1. वर्टिकल खेती को सामान्य भाषा में खड़ी खेती भी कह सकते हैं। यह खुले में हो सकती है और इमारतों व अपार्टमेंट की दीवारों का उपयोग भी छोटी-मोटी फसल उगाने के लिए किया जा सकता है।
2. वर्टिकल फार्मिंग एक मल्टी लेवल प्रणाली है। इसके तहत कमरों में एक बहु-सतही ढांचा खड़ा किया जाता है, जो कमरे की ऊंचाई के बराबर भी हो सकता है। वर्टिकल ढांचे के सबसे निचले खाने में पानी से भरा टैंक रख दिया जाता है।
3. टैंक के ऊपरी खानों में पौधों के छोटे-छोटे गमले रखे जाते हैं। पंप के जरिए इन तक काफी कम मात्रा में पानी पहुंचाया जाता है। इस पानी में पोषक तत्व पहले ही मिला दिए जाते हैं। इससे पौधे जल्दी-जल्दी बढ़ते हैं। एलइडी बल्बों से कमरे में बनावटी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है।
4. इस प्रणाली में मिट्टी की जरूरत नहीं होती। इस तरह उगाई गई सब्जियां और फल खेतों की तुलना में ज्यादा पोषक और ताजे होते हैं। अगर ये खेती छत की जाती है तो इसके लिए तापमान को नियंत्रित करना होगा।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

3. विश्वविद्यालय के चौयरमेन सुनील शर्मा ने बताया कि अभी प्रारंभिक स्तर पर सब्जियों का उत्पादन होने लगा है लेकिन जल्दी ही अन्य कृषि उत्पादों के लिए शोध शुरू किए जा रहे है। दावा है कि राजस्थान में यह पहला शोध है जो पूरी तरह से सफल रहा है। आने वाले समय में पूरे पश्चिमी भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों यह शोध कारगर साबित हो सकता है।
4. केंद्र के कोऑर्डिनेटर अभिषेक शर्मा ने बताया की हाइड्रोपोनिक तकनीक से कम पानी और बिना मिट्टी की इस फसल की पैदावार रोगरहित होती है। साथ ही इसमें किसी तरह की रसायन खाद का उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऑर्गेनिक होने के कारण ये सब्जियां थोड़ी महंगी हो सकती है।

IPL इतिहास के ये हैं 10 सबसे महंगे खिलाड़ी

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 10वां सीजन इस साल खेला जाना है। अभी तक खेले गए 9 सीजन और 10वें सीजन की नीलामी की बात करें तो खिलाड़ियों का प्राइस टैग हर बार ही चर्चा में बना रहता है। सोमवार को नीलामी में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज टी. मिल्स के दाम सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। इन दोनों का दाम बेस प्राइस से काफी ऊपर चला गया। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजी ने जमकर पैसा बहाया है। 10 साल के राउंड में ये आखिरी नीलामी होगी। आईपीएल के पहले सीजन साल 2008 से 10वें सीजन साल 2017 तक के सबसे महंगे खिलाड़ी भारत के सिक्सर किंग युवराज सिंह रहे हैं। आगे की स्लाइड में पढ़ें स्टोक्स और मिल्स कैसे शामिल हुए सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में...

क्या है?

1. स्टोक्स आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। स्टोक्स जिस तरह की फॉर्म में हैं ऐसे में उन पर फ्रेंचाइजी का पैसा बहाना लाजमी माना जा रहा था। पुणे सुपरजायंट्स ने स्टोक्स को 14.5 करोड़ रुपये में खरीदा है। वहीं टी. मिल्स भी टॉप 10 सबसे महंगे खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं, उन्हें रॉयल चौलेंजर बेंगलोर ने 12 करोड़ में खरीदा।
2. बेन स्टोक्स ने दूसरे नंबर आने के साथ ही टीम इंडिया के महेंद्र सिंह धौनी को तीसरे नंबर पर कर दिया है।
3. टी मिल्स ने टॉप 5 में जगह बनाने के साथ गौतम गंभीर को एक नंबर नीचे ढकेल दिया है।

टॉप-10 सबसे महंगे बिके खिलाड़ियों पर-

	खिलाड़ी का नाम और फ्रेंचाइजी टीम	रुपये	साल
1	युवराज सिंह (दिल्ली डेयरडेविल्स)	16 करोड़	2015
2	बेन स्टोक्स (राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स)	14.5 करोड़	2017
3	महेंद्र सिंह धौनी (राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स)	12.5 करोड़	2016
4	दिनेश कार्तिक (दिल्ली डेयरडेविल्स)	12.5 करोड़	2014
5	टी मिल्स (आरसीबी)	12 करोड़	2017
6	गौतम गंभीर (केकेआर)	11.05 करोड़	2011
7	यूसुफ पठान (केकेआर)	9.66 करोड़	2011
8	रोबिन उथप्पा (पुणे वॉरियर्स)	9.66 करोड़	2011
9	रोहित शर्मा (मुंबई इंडियन्स)	9.2 करोड़	2011
10	रविंद्र जडेजा (चेन्नई सुपर किंग्स)	9.2 करोड़	2012

हथियारों की बिक्री में भारत ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा

दुनिया में हथियारों की बिक्री ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 1947 में शीतयुद्ध की शुरुआत के दौरान इतने बड़े पैमाने पर सैन्य सौदे हुए थे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस ने पांच वर्षों (2012-16) के दौरान हथियारों के सौदों का आकलन कर इसकी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में मध्यपूर्व संकट, दक्षिण चीन सागर और रूस से पड़ोसी देशों के खतरे को हथियार सौदे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह माना गया है।

भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा

1. 13 % हथियार खरीदे भारत ने विश्व में हुए कुल सौदों में
2. 43 % बढ़ोतरी हथियार खरीद में पिछले पांच साल में
3. 60 % हथियार रूस से खरीद रहा भारत, अमेरिका उसके बाद
4. 7.7 % की बढ़ोतरी एशिया-ओसियाना में सैन्य सौदों में

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मसले पर सुनवाई करते हुए प्राथमिक तौर पर आद्योगिक यूनिटों के ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित न करने पर नाराजगी जाहिर करते हुये राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सभी आद्योगिक इकाइयों को कॉमन नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। जिससे औद्योगिक यूनिटों की ओर से प्राथमिक तौर पर गन्दगी के निस्तारण की व्यवस्था के बारे में पता लगाया जा सके।

क्या है?

1. मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने अगले तीन माह में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाने वाले औद्योगिक यूनिटों की बिजली सप्लाई काटने का निर्देश दिया।
2. कोर्ट ने सख्त अंदाज में कहा कि अगर औद्योगिक यूनिट प्राथमिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा रही हैं, तो उन्हें किसी भी तरह देश में अपने उद्योग चलाने की अनुमति नही मिलनी चाहिए।
3. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यदि औद्योगिक ईकाईयों में कचरा शोधन ईकाईयां सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं तो अब उन्हें और काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम और दूसरे स्थानीय निकायों से औद्योगिक इकाइयों के ट्रीटमेंट प्लांट लगाने को लेकर जागरुकता प्रचार चलाने की बात कही। साथ ही कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐसा नहीं करने वाली यूनिटों के खिलाफ आपराधिक और सिविल मामले के तहत केस दर्ज करने का निर्देश दिया।
5. कोर्ट ने ट्रीटमेंट की प्रगति की जानकारी एनजीटी की बेंच को देने की बात कही गयी। कोर्ट में राज्यों की ओर से कहा गया कि तीन माह के नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड औद्योगिक यूनिट की प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लाट के बारे में जानकारी हासिल करेगें।

शुरोजेली ने नगालैंड के सीएम पद की ली शपथ

नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के नेता शुरोजेली लीजित्सू नगालैंड के मुख्यमंत्री बन गए। उनको राजभवन में राज्यपाल पीबी आचार्य ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।

क्या है?

1. इसके पहले सत्ताधारी गठबंधन डेमोक्रेटिक एलायंस ऑफ नगालैंड (डीएएन) के 59 विधायकों ने उनको सर्वसम्मति से नेता चुना था। शुरोजेली एनपीएफ के अध्यक्ष हैं और उनको टीआर जीलियांग की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया है।
2. जीलियांग ने रविवार को कई आदिवासी समूहों के भारी विरोध के बीच मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ये समूह राज्य सरकार के 33 फीसद महिला आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने के कदम का विरोध कर रहे थे।
3. इस मसले पर सरकार और आदिवासी समूहों के बीच जारी गतिरोध को दूर करने के लिए 15 फरवरी को 42 विधायकों ने शुरोजेली को विधायक दल का नेता बनाए जाने का समर्थन किया था।
4. शुरोजेली डीएएन के अध्यक्ष भी हैं। वह आठ बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने 2013 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था।

भारत की पांच कंपनियां हाइपरलूप ट्रेन चलाने की इच्छुक

विमानों जैसी रफ्तार वाली हाइपरलूप ट्रेन प्रणाली को हकीकत की जमीन पर उतारने में पांच भारतीय कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। इनमें डिनक्लिक्स ग्राउंडवर्क्स कंपनी दिल्ली-मुंबई हाइपरलूप का निर्माण करना चाहती है। हाइपरलूप ट्रेन 1317 किलोमीटर की इस दूरी को मात्र 55 मिनट में पूरा करेगी। अन्य कंपनियों में ऐकॉम ने 334 किलोमीटर लंबे बंगलूर-चेन्नई रूट का प्रस्ताव दिया है। हाइपरलूप यह दूरी केवल 20 मिनट में तय करेगी। लक्स हाइपरलूप नेटवर्क ने बंगलूर-तिरुवनंतपुरम के 636 किलोमीटर रूट में रुचि दिखाई है। हाइपरलूप इसे 41 मिनट में तय करेगी।

क्या है?

1. हाइपरलूप इंडिया मुंबई-बंगलूर-चेन्नई के 1102 किलोमीटर लंबे रूट को 50 मिनट में पूरा करने के लिए काम करना चाहती है। इसी तरह इंफी-अल्फा ने 334 किलोमीटर लंबे बंगलूर-चेन्नई रूट को 20 मिनट में पूरा करने के लिए हाईपरलूप कारीडोर बनाने का दावा पेश किया है। इन सभी कंपनियों ने हाइपरलूप ट्रेनों के जरिए यात्री एवं माल परिवहन में सालाना 15 फीसद बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

2. हाइपरलूप तकनीक में अग्रणी कंपनी हाईपरलूप वन ने दुनिया भर के देशों से इस तकनीक की परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। जिसके जवाब में 90 देशों से 2600 कंपनियों ने अपने प्रस्ताव भेजे थे। इनके मूल्यांकन के बाद जिन 26 अरब डालर के संभावित निवेश वाले 35 प्रस्तावों को गंभीर माना गया है। इनमें भारत की सर्वाधिक कंपनियां शामिल हैं।
3. हाइपरलूप तकनीक अभी अभिकल्पना के स्तर पर है। इसे व्यावहारिक शक्ल दिया जाना बाकी है। लेकिन हाइपरलूप वन को पूरा भरोसा है कि एक बार इसका पायलट प्रोजेक्ट तैयार हो गया तो यह तकनीक पूरी दुनिया में छा जाएगी। भारत के अलावा अमेरिका और दुबई में भी इस तकनीक पर काम हो रहा है।
4. हाइपरलूप चुंबकीय शक्ति पर आधारित तकनीक है। जिसके तहत खंभों के ऊपर (एलीवेटेड) पारदर्शी ट्यूब बिछाई जाती है। इसके भीतर बुलेट जैसी शक्ल की लंबी सिंगल बोगी हवा में तैरते हुए चलती है। चूंकि इसमें घर्षण बिल्कुल नहीं होता, लिहाजा इसकी रफ्तार 1100-1200 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे भी अधिक हो सकती है। इसमें बिजली का खर्च बहुत कम है। जबकि प्रदूषण बिल्कुल नहीं है।
5. भारत में हाइपरलूप को बढ़ावा देने के लिए हाइपरलूप वन की ओर से मंगलवार को राजधानी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। इसमें रेलमंत्री सुरेश प्रभु तथा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शिरकत की। प्रभु ने हाइपरलूप को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। उन्होंने कहा 'हाइपरलूप' को लेकर हम 'हाइपर' नहीं हैं, लेकिन इसे 'लूप' में लेकर चल रहे हैं। क्योंकि ऐसी नई तकनीकों को अपनाना आसान नहीं है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)